भूख से लड़ाई में असफल भारत

डॉ. राम प्रताप गुप्ता

खाद्य एवं कृषि संगठन की सितंबर माह में सम्पन्न वार्षिक बैठक में उसके अध्यक्ष ने विश्व को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर हमने खाद्यान्न और कृषि उत्पादन में वृद्धि करने के समुचित प्रयास न किए तो सन 2015 तक विश्व में भूख और कुपोषण के स्तर में 50 प्रतिशत कमी लाने का लक्ष्य हासिल नहीं किया जा सकेगा।

भूख और कुपोषण में कमी लाने का मुद्दा भारत के लिए और भी महत्वपूर्ण है क्योंकि विश्व की कुल कुपोषित आबादी का एक-तिहाई हिस्सा भारत में निवास करता है और यहां कुपोषण का स्तर कई अन्य अधिक पिछड़े अफ्रीकी राष्ट्रों से भी अधिक है। तृतीय राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण और अन्य स्रोतों से प्राप्त आंकड़े बताते है कि देश के आधे बच्चे और एक-तिहाई आबादी कुपोषण और भूख का शिकार है। मध्यप्रदेश की बात करें तो यहां समय के साथ-साथ कुपोषण की समस्या अधिकाधिक उग्र होती जा रही है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षणों के अनुसार यहां सन 1993-94 में 48 प्रतिशत बच्चे कुपोषण के शिकार थे जो सन 1999-2000 में बढ़कर 54 प्रतिशत और सन 2005-06 में 60 प्रतिशत हो गए। यह प्रतिशत पूरे राष्ट्र में सर्वाधिक है।

देश में कुपोषण के स्तर के इतने ऊंचे होने तथा स्वास्थ्य सेवाओं की अपर्याप्ता के कारण 19.5 लाख बच्चे प्रति वर्ष पांचवे जन्म दिन के पूर्व ही मौत के शिकार हो जाते हैं और विश्व में इस आयु वर्ग में मरने वाले कुल बच्चों में 20 प्रतिशत बच्चे भारतीय होते है। हमने भूख और कुपोषण की समस्या को किस प्रकार अनदेखा किया है, इसका पता इस तथ्य से भी लगता है कि गर्भावस्था में माता को समुचित पोषण न मिलने के कारण हमारे यहां नवजात शिशु मृत्यु की दर 72 प्रति हज़ार है जो श्रीलंका की तुलना में 3 गुना अधिक है।

देश में कुपोषण के कारणों की बात करें, तो पिछले वर्षों में सरकार द्वारा कृषि की उपेक्षा प्रमुख कारण के रूप में सामने आती है। कृषि की उपेक्षा का परिणाम है कि 1990-2007 की अवधि में देश में खाद्यान्न उत्पादन में 1.2 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ही वृद्धि हुई जबकि इसी अवधि में हमारी आबादी 1.9 प्रतिशत की दर से बढ़ी है। इसके चलते देश में खाद्यान्न की उपलब्धता सन 1990-91 में 171 किलोग्राम प्रति व्यक्ति से गिरकर सन 2005-06 में 150 किलोग्राम ही रह गई। बाद के वर्षों में इस मात्रा में थोड़ी परन्तु अपर्याप्त वृद्धि ही हुई है। निरामिष भारत में प्रोटीन के प्रमुख स्रोत दालों का उत्पादन भी इसी अवधि में 15.3 किलोग्राम से गिरकर 12 किलोग्राम प्रति व्यक्ति ही रह गया। खाद्यान्न उपलब्धता में गिरावट के इन आंकड़ों की पृष्ठभूमि में खाद्यान्न उत्पादन को प्रोत्साहित करने की नीति अपनाना चाहिए था, परन्तु सरकार निर्यात हेतु फूलों, तथा फलों के उत्पादन को प्रोत्साहित करती रही है। परिणामस्वरूप आबादी में सतत वृद्धि की इस अवधि में खाद्यान्न के अंतर्गत क्षेत्र में 60 लाख हैक्टर की कमी आई। कहा जाता है कि फूलों, फलों जैसे उत्पादों का निर्यात करके बदले में हम खाद्यान्न का आयात कर सकते हैं, परन्तु इस अवधि में खाद्यान्न की वैश्विक कीमतों में वृद्धि तथा प्रमुख निर्यातक अमरीका द्वारा खाद्यान्न से जैव ईंधन बनाने की नीति के कारण यह भी आसान नहीं था।

इस तरह देश में खाद्यान्न की प्रति व्यक्ति उपलब्धता में कमी ही देश में भूख के इतने ऊंचे स्तर का कारण बनी रही और हाल ही सम्पन्न संयुक्त राष्ट्र संघ एवं एक्शन एड नामक संगठन की बैठकों में भारत को भूख के विरुद्ध संघर्ष करने में असफल राष्ट्रों की श्रेणी में शामिल किया है। भूख के विरुद्ध संघर्ष के सूचकांकों के आधार पर एक्शन एड ने ब्राज़ील और चीन को जहां शीर्ष क्रम पर रखा है, वहीं भारत को काफी नीचे बाइसवें स्थान पर रखा गया है। ब्राज़ील में कुपोषित बच्चों की संख्या में 73 प्रतिशत की कमी आई है।

ब्राज़ील खाद्य बैंकों तथा सामुदायिक रसोई घरों के संचालन तथा लघु एवं सीमान्त कृषकों को उदार सहायता के माध्यम से यह सफलता हासिल कर सका है। इस दृष्टि से भारत को इथोपिया एवं लेसोथो जैसे राष्ट्रों के साथ रखा गया है जहां नब्बे के दशक की तुलना में अब 3 करोड़ अधिक लोग भूख के शिकार है।

अतीत की नाकामी के अलावा आने वाले वर्षों में भारत को और अधिक प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करना होगा। वैश्विक तापमान में वृद्धि तथा उसके परिणामस्वरूप आए मौसम परिवर्तन से उसे खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि करने तथा उसे बनाए रखने में नई प्रतिकूलताओं का सामना करना पड़ेगा। वैश्विक तापमान में वृद्धि के फलस्वरूप देश में सूखे और बाढ़ की संभावनाएं बढ़ती जा रही हैं।

इस वर्ष कर्नाटक एवं आंध्र जैसे राज्यों के बड़े भूभाग बाढ़ में डूब जाने से खरीफ की फसल नष्ट हो गई है, वहीं देश के अन्य भागों में यही स्थिति सूखे एवं अल्प वर्षा के कारण बनी है। पिछले वर्ष कोसी नदी में आई भयंकर बाढ़ और मार्ग परिवर्तन से लाखों हैक्टर फसल नष्ट हो गई थी, वहीं देश के अन्य भागों में सूखे की स्थिति थी। ये संकेत बताते हैं कि आने वाले वर्षों में भारत को भूख के विरुद्ध संघर्ष में नई और कठिन परिस्थितियों का सामना करना होगा, परन्तु इस दिशा में तैयारी के कोई संकेत नहीं हैं।

देश में भूख व कुपोषण के विरुद्ध सफल संघर्ष के लिए कृषि विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी ही होगी। कृषि विकास की उपेक्षा की अब तक की नीतियों को उलट देना होगा। गौरतलब है कि भूख के विरुद्ध संघर्ष में हमें तभी सफलता मिलेगी जब उत्पादन वृद्धि के साथ-साथ गरीबों की खाद्यान्न तक सहज पहुंच भी बने।

वर्तमान में सरकार ने गरीबों को रियायती कीमतों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने की व्यवस्था की है। लेकिन अनेक विद्वानों ने देश में गरीबी के वर्तमान मापदण्डों को दोषपूर्ण बताया है। सरकार के अनुसार देश में गरीबी मात्र 27 प्रतिशत है जबकि सेनगुप्ता समिति के अनुसार देश के 60 प्रतिशत लोग अपने उपभोग पर प्रतिदिन 10 रुपए ही खर्च कर पाते हैं और 78 प्रतिशत लोग प्रतिदिन 20 रुपए से कम खर्च करते हैं। अध्ययन करने पर पाया गया है कि सरकार द्वारा गरीबी की रेखा से नीचे जिन लोगों को शामिल किया जाता है, उनमें अनेक संपन्न लोग हैं। गरीबी कार्ड धारकों में ऐसे सम्पन्न लोगों का प्रतिशत आंध्र में 39.5, कर्नाटक में 29.2, केरल में 23.2 प्रतिशत है, वहीं राजस्थान में यह प्रतिशत 3.7, तमिलनाडु में 3.5 और हरियाणा में 1.8 प्रतिशत ही है।

स्पष्ट है कि वर्तमान में गरीबों में भूख और कुपोषण में कमी लाने के जो भी प्रयास किए जा रहे है, वे भी आधे-अधूरे और दोषपूर्ण हैं और उन तक गरीबों की समुचित पहुंच भी नहीं है और इनका लाभ गैर-गरीबों द्वारा हड़पा जा रहा है। ऐसे में भारत को भूख के विरुद्ध संघर्ष में असफल राष्ट्रों की जमात में शामिल किए जाने पर कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए।

आज़ादी के इन 60 वर्षों में भी देश के नागरिकों को भूख और कुपोषण से मुक्ति दिलाने में असफलता का एक दुष्परिणाम यह भी हुआ है कि जहां दुनिया के अन्य राष्ट्र समय के साथ अपने नागरिकों की ऊंचाई में औसतन 1 इंच की वृद्धि कर सकने में सफल रहे हैं, वहीं भारत की इस दिशा में प्रगति नगण्य रही है। केवल सम्पन्न परिवारों में नई पीढ़ी के युवा अपने माता-पिता से अधिक ऊंचे दिखाई देते हैं। विश्व के अन्य देशों के नागरिकों की औसत ऊंचाई में वृद्धि और भारत के नागरिकों के इस दिशा में असफल रहने का एक परिणाम यह भी हुआ है कि भारतीय अन्य राष्ट्रों के नागरिकों की तुलना में ठिगने होते जा रहे हैं।

उपरोक्त विश्लेषण से यह स्पष्ट हो जाता है कि भारत को आने वाले वर्षों में भूख और कुपोषण से मुक्ति के लक्ष्य को अपनी विकास नीतियों में सर्वोच्च स्थान देना होगा। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो भारत के एक महाशक्ति के रूप में नहीं बल्कि भूखे, कुपोषितों के राष्ट्र के रूप में उभरने का खतरा है। समय है कि भारत अपनी विकास नीतियों में कृषि विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करे तथा खाद्यान्नों तक गरीबों, कुपोषितों की समुचित पहुंच बनाने की व्यवस्था करे। यही राष्ट्र के व्यापक और दीर्घकालीन हित में भी होगा। ***(स्रोत फीचर्स)***